



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 86]

नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 20, 2018/फाल्गुन 29, 1939

No. 86]

NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 20, 2018/PHALGUNA 29, 1939

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

जांच शुरुआत संबंधी अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 मार्च, 2018

(निर्णायक समीक्षा)

(मामला सं. एसएसआर 4/2018)

विषय : चीन जनवादी गणराज्य और यूएसए के मूल की अथवा वहां से निर्यातित पेरोक्सोसल्फेट (परसल्फेट) के आयातों पर लागू पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा की शुरुआत

फा. सं. 7/5/2018-डीजीएडी.—1995 में यथा संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे एतद्पश्चात् अधिनियम कहा गया है) और समय-समय पर यथा संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति निश्चरिण) नियमावली, 1995 (जिसे एतद्पश्चात् नियमावली भी कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे एतद्पश्चात् 'प्राधिकारी' भी कहा गया है), चीन जन गण, जापान, संयुक्त राज्य अमरीका और ताइवान के मूल की अथवा वहां से निर्यातित "पेरोक्सोसल्फेट्स" (जिसे एतद्पश्चात् संबद्ध वस्तुएं भी कहा गया है) के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करते हैं।

2. यतः चीन और जापान से संबद्ध वस्तु के आयातों से संबंधित मूल जाँच प्राधिकारी द्वारा की गई थी जिसके लिए दिनांक 20.07.2007 की अधिसूचना सं. 14/1/2006-डीजीएडी द्वारा पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश की गई थी। तत्पश्चात् निर्णायक समीक्षा जाँच में शुल्क की समीक्षा की गई और सिफारिशों को दिनांक 12.3.2013 की अधिसूचना सं. 15/9/2011-डीजीएडी द्वारा अधिसूचित किया गया। तदनुसार, शुल्क लगाने वाली सीमाशुल्क अधिसूचना सं 11/2013-सीमाशुल्क (एडीडी), दिनांक 16.05.2013 जारी की गई और शुल्क 15.5.2018 तक अब भी लागू है।

3. यतः प्राधिकारी द्वारा ताइवान, तुर्की और यूएसए के विरुद्ध एक अन्य पाटनरोधी जाँच की गई थी जिसके लिए केवल ताइवान और यूएसए के विरुद्ध दिनांक 4.3.2014 की अधिसूचना सं. 14/9/2012-डीजीएडी द्वारा पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश की गई थी। तदनुसार, सीमाशुल्क अधिसूचना सं 22/2014-सीमाशुल्क (एडीडी) दिनांक 16.05.2014 द्वारा शुल्क लगाया गया और वह अब भी यूएसए और ताइवान के विरुद्ध 15.5.2019 तक अब भी लागू है।

4. यतः नियम 23(1ख) के अनुसार संबद्ध वस्तु के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क को लागू रखने के लिए यतः वर्तमान याचिका मै. केलिबर कैमिकल्स प्रा. लि., मै. वीआर परसल्फेट्स और मै. योयो कैमिकल्स द्वारा चीन जन. गण., जापान, यूएसए और ताइवान के विरुद्ध संयुक्त समीक्षा किए जाने की मांग करने के लिए एक याचिका दायर की गई है।

5. जबकि प्राधिकरण, तथ्यों और आंकड़ों की जांच के बाद याचिका में प्रस्तुत किए गए निर्णय के बाद, इस निर्णय पर आया है, वर्तमान एंटी डंपिंग कर्तव्यों की समाप्ति से जापान और ताइवान से आयात किसी भी क्षति या घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचाने की संभावना नहीं है। हालाँकि, तथ्यों और आंकड़ों के आधार पर प्राधिकरण का मानना है कि चीन के जनसंपर्क और संयुक्त राज्य अमेरिका से उत्पन्न या निर्यात किए जाने वाले विषय वस्तु के संबंध वस्तु के संबंध वर्तमान एंटी डंपिंग कर्तव्यों की समाप्ति में लागू शुल्क को जारी रखने की समीक्षा की आवश्यकता है।

संबद्ध देश

6. इस जांच में शामिल देश चीन जन. गण और यूएसए है।

विचाराधीन उत्पाद

7. वर्तमान जाँच में विचाराधीन उत्पाद पेरॉक्सोसल्फेट है और जिसे आम तौर पर परसल्फेट के रूप में जाना जाता है। विचाराधीन उत्पाद मूल जाँच में विचार किए गए के समान है।

8. परसल्फेट घनिष्ठता से जुड़े यौगिकों का समूह है। इन्हें अल्कली मेटल साल्ट के रूप में उत्पादित किया जाता है। विचाराधीन उत्पाद को विभिन्न ग्रेडों अर्थात् अमोनियम परसल्फेट (एपीएस), पोटेशियम परसल्फेट (पीपीएस) और सोडियम परसल्फेट (एसपीएस) में वर्गीकृत किया जाता है। ये ग्रेड रसायन के समान समूह अर्थात् परसल्फेट्स और परक्सोसल्फेट्स से संबंधित हैं। इन परसल्फेटों का रासायनिक फार्मूला क्रमशः (एनएच₄)₂एस₂ओ₈, के₂एस₂ओ₈, एनए₂एस₂ओ₈ हैं। इन तीन प्रकार के परसल्फेटों का समान अंतिम उपयोग होता है जो वस्त्र, सौंदर्य प्रसाधन, रसायन उद्योग और निःस्सारण उपचार संयंत्रों के लिए आरंभक और आक्सीकरण एजेंट के रूप में होता है। तथापि इन्हें विभिन्न ग्रेडों की विशिष्ट जरूरतों के अनुसार एक-दूसरे से प्रतिस्थापित किया जा सकता है।

9. परसल्फेटों को सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अध्याय 28 में एचएस कोड 2833 40 00 के अधीन वर्गीकृत किया जाता है। तथापि, यह वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और वर्तमान जाँच के दायरे पर किसी भी प्रकार से बाध्यकारी नहीं है।

समान वस्तु

10. समान वस्तु के संबंध में नियम 2(घ) में निम्नानुसार व्यवस्था है:-

“समान वस्तु” से ऐसी वस्तु अभिप्रेत है जो भारत में पाटन के कारण जांच के अंतर्गत वस्तु के सभी प्रकार से समरूप या समान है अथवा ऐसी वस्तु के न होने पर अन्य वस्तु जोकि यद्यपि सभी प्रकार से समनुरूप नहीं है परंतु जांचाधीन वस्तुओं के अत्यधिक सदृश विशेषताएं रखती हैं;

11. याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि संबद्ध देशों से निर्यातित और भारतीय उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु के बीच कोई ज्ञात अंतर नहीं है। इन दोनों उत्पादों में भौतिक और रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्य और प्रयोग, उत्पाद विनिर्देशन, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन तथा टैरिफ वर्गीकरण जैसे मापदंडों की दृष्टि से तुलनीय विशेषताएं हैं।

घरेलू उद्योग और उसकी स्थिति

12. यह याचिका मै. केलिबर कैमिकल्स प्रा. लि., मै. वीआर परसल्फेट्स और मै. योयो कैमिकल्स द्वारा दायर की गई है। याचिकाकर्ता कंपनियों अर्थात् मै. केलिबर कैमिकल्स प्रा. लि. और मै. वीआर परसल्फेट्स ने याचिका में पूरी वित्तीय सूचना उपलब्ध कराई है जिस पर प्रथम दृष्टया पाटन और घरेलू उद्योग को हुई परिणामी क्षति का विश्लेषण करने के लिए विचार

किया गया है। तीसरे याचिकाकर्ता मै. योयो कैमिकल्स ने पूरी सूचना नहीं दी है और इसलिए उन्हें घरेलू उद्योग माना गया है परंतु पाटन और क्षति के लिए उनके आकड़ों पर विचार नहीं किया गया है। जाँच की प्रक्रिया के दौरान उन्हें पूरी सूचना देने का अवसर दिया जाएगा जिस पर जाँच के अंतिम परिणाम से पहले विचार किया जाएगा।

13. यह पाया गया है कि याचिकाकर्ता कंपनियों का उत्पादन देश में संबद्ध वस्तु के भारतीय उत्पादन का 86 प्रतिशत बनता है। प्रस्तुत सूचना के आधार पर, प्राधिकारी नोट करते हैं कि याचिकाकर्ता कंपनियों ने पीओआई के दौरान संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु का कोई आयात नहीं किया है। इसलिए, प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 2(ख) के अर्थ के भीतर याचिकाकर्ता कंपनियों को घरेलू उद्योग माना है और आवेदन संबंधित नियमावली के नियम 5 के अनुसार योग्यता संबंधी मापदंडों को पूरा करता है।

निर्णायक समीक्षा की शुरुआत

14. प्रस्तुत किए गए विधिवत रूप से साक्ष्यांकित आवेदन को ध्यान में रखते हुए और पाटनरोधी नियमावली के नियम 23 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9 क (5) के अनुसार प्राधिकारी एतद्वारा निर्णायक समीक्षा जाँच की शुरुआत करते हैं ताकि समीक्षा की जा सके कि क्या संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के संबंध में लागू शुल्क को जारी रखने की आवश्यकता की समीक्षा की जा सके और इस बात की जाँच की जा सके कि क्या लागू शुल्क को हटाये जाने से पाटन के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने और घरेलू उद्योग को क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है।

जाँच अवधि

15. आवेदक द्वारा जाँच अवधि (पीओआई) के रूप में 1 अक्टूबर, 2016 से 30 सितंबर, 2017 (12 महीने) और क्षति जाँच अवधि का अप्रैल 2014 – मार्च, 2015, अप्रैल 2015 – मार्च, 2016, अप्रैल 2016 – मार्च, 2017 के रूप में प्रस्ताव किया गया है। पाटन और क्षति की संभावना निर्धारित करने के लिए पीओआई से आगे के आकड़ों की भी जाँच की जाएगी।

प्रक्रिया

16. इस समीक्षा में दिनांक 12.03.2013 की अधिसूचना सं 15/9/2011-डीजीएडी और दिनांक 4.3.2014 की अधिसूचना सं 14/9/2012-डीजीएडी के अधीन यथा अधिसूचित सभी पहलू शामिल होंगे।

17. संबंधित नियमावली के नियम 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19 और 20 के उपबंध आवश्यक संशोधनों के साथ इस समीक्षा पर लागू होंगे।

18. प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत करते समय, संबद्ध देश में उत्पादक/निर्यातक को विनिर्माण, उत्पादन और घरेलू बाजार में संबद्ध वस्तु की बिक्री और भारत और अन्य देशों को निर्यात के संबंध में बाजार दशाओं की मौजूदगी को प्रदर्शित करना होगा। इस प्रयोजनार्थ, उत्पादक/निर्यातक निम्नलिखित के संबंध में पर्याप्त सूचना उपलब्ध करा सकते हैं:

- क. कीमत, लागत, कच्ची सामग्री सहित निविष्टि, प्रौद्योगिकी और श्रम की लागत, उत्पादन, बिक्री और निवेश के संबंध में निर्णय बाजार संकेतकों जो आपूर्ति और मांग को दर्शाते हैं और राज्य के किसी हस्तक्षेप के बिना लिये जाते हैं और क्या प्रमुख निविष्टियों की लागत बाजार मूल्य को पर्याप्त रूप से प्रदर्शित करती है।
- ख. उत्पादन लागत और वित्तीय स्थिति किसी विकृति से प्रभावित नहीं हैं।
- ग. उत्पादक/निर्यातक दिवालिया और संपत्ति कानून के अधीन हैं जो फर्मों के प्रचालन के लिए विधिक निश्चितता और स्थिरता की गारंटी देते हैं।
- घ. विनिमय दर में परिवर्तन बाजार दर पर किये जाते हैं।

सूचना प्रस्तुत करना

19. संबद्ध देशों में ज्ञात निर्यातकों, भारत में स्थित उनके दूतावास के जरिए संबद्ध देशों की सरकारों, भारत में संबद्ध वस्तु के आयातकों व प्रयोक्ताओं को नीचे निर्धारित की गई समय सीमा के भीतर विहित प्रपत्र में एवं ढंग से समस्त संगत सूचना निम्नलिखित को प्रस्तुत करने और प्राधिकारी को अपने विचारों से अवगत कराने का अनुरोध किया गया है:

भारत सरकार
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय
चौथा तल, जीवन तारा बिल्डिंग,
5, संसद मार्ग, नई दिल्ली 110001-

20. कोई अन्य हितवद्ध पक्षकार भी जांच से संगत कोई अनुरोध नीचे दी गई समय सीमा के भीतर निर्धारित ढंग और पद्धति से प्रस्तुत कर सकता है। प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी पक्षकार को अन्य पक्षों को उसे उपलब्ध कराने के लिए उसका अगोपनीय अंश भी प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

समय-सीमा

21. वर्तमान समीक्षा से संबंधित कोई सूचना और सुनवाई के लिए कोई अनुरोध इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से चालीस दिनों (40 दिनों) के भीतर उपर्युक्त पते पर प्राधिकारी के पास लिखित में भेजी जानी चाहिए। यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है अथवा प्राप्त सूचना अधूरी होती है, तो प्राधिकारी पाटनरोधी नियमावली के अनुसार, रिकॉर्ड में "उपलब्ध तथ्यों" के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।

22. सभी हितवद्ध पक्षकारों को एतद्वारा सलाह दी जाती है कि वे इस जाँच की शुरुआत की तारीख से 40 दिनों के भीतर वर्तमान मामले में अपने हित (हित के स्वरूप सहित) की सूचना दें और प्रश्नावली के अपने उत्तर दायर करें तथा पाटनरोधी उपायों को जारी रखने की जरूरत या अन्यथा के संबंध में घरेलू उद्योग के आवेदन पर अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत करें।

गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

23. यदि प्रश्नावली के उत्तर/अनुरोधों के किसी भाग के संबंध में गोपनीयता का दावा किया जाता है तो ऐसे मामले में निम्नानुसार दो अलग-अलग सैट (क) गोपनीय रूप से अंकित एक सैट (शीर्षक, सूची, पृष्ठ संख्या आदि); और (ख). अगोपनीय रूप में अंतिम दूसरा सैट (शीर्षक, सूची, पृष्ठ संख्या आदि) प्रस्तुत करना होगा। दी गई समस्त सूचना पर स्पष्ट रूप से प्रत्येक पृष्ठ पर "गोपनीय "या" अगोपनीय "अंकित होना चाहिए और उनकी साफ्ट प्रतियां होनी चाहिए।

24. किसी गोपनीय अंकन के बिना प्रस्तुत सूचना को प्राधिकारी द्वारा अगोपनीय माना जाएगा और प्राधिकारी अन्य हितवद्ध पक्षकारों को ऐसी अगोपनीय सूचना का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे। सभी हितवद्ध पक्षों द्वारा गोपनीय पाठ की दो (2) प्रतियां और अगोपनीय पाठ की दो (2) प्रतियां प्रस्तुत करना जरूरी होगा।

25. गोपनीय होने का दावा की गई सूचना के लिए, सूचना प्रदाता को प्रदत्त सूचना के साथ ऐसे कारणों का विवरण प्रस्तुत करना होगा कि उस सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता है और/या ऐसी सूचना का सारांशकरण क्यों संभव नहीं है।

26. अगोपनीय रूपांतरण को उस सूचना, जिसके बारे में गोपनीयता का दावा किया गया है, पर निर्भर रहते हुए अधिमानतः सूचीबद्ध /रिक्त छोड़ी गई और सारांशीकृत गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय रूपांतरण की अनुकृति होना अपेक्षित है। अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना की विषय वस्तु को समुचित ढंग से समझा जा सके। तथापि, आपवादिक परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रदाता पक्षकार यह इंगित कर सकते हैं कि ऐसी सूचना का सारांश संभव नहीं है और प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार इस आशय के कारणों का एक विवरण उपलब्ध कराया जाना चाहिए कि सारांश क्यों संभव नहीं है।

27. प्रस्तुत सूचना के स्वरूप की जांच करने के बाद प्राधिकारी गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध अपेक्षित नहीं है अथवा सूचना प्रदाता उक्त सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्य रूप में अथवा सारांश रूप में उसके प्रकटन को प्राधिकृत करने का अनिच्छुक है तो वह ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।

28. सार्थक अगोपनीय रूपांतरण के बिना या गोपनीयता के दावे के बारे में यथोचित कारण के विवरण के बिना किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा। प्रदत्त सूचना की गोपनीयता की जरूरत से संतुष्ट होने और

उसे स्वीकार कर लेने के बाद प्राधिकारी ऐसी सूचना के प्रदाता पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना किसी पक्षकार को उसका प्रकटन नहीं करेंगे।

सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

29. नियम 6 (7) के अनुसार कोई हितबद्ध पक्षकार उस सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकता है जिसमें अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय रूपांतरण रखे गए हैं।

असहयोग

30. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है अथवा उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी ऐसे पक्षकार को असहयोगी घोषित कर सकते हैं और अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं तथा केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

सुनील कुमार, अपर सचिव एवं निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES)

INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 20th March, 2018

(Sunset Review)

(Case No. SSR 4/2018)

Subject: Initiation of Sunset Review of Anti-dumping Duty imposed on imports of Peroxosulphates (Persulphate) originating in or exported from China PR and USA.

F. No. 7/5/2018-DGAD.—Having regard to the Customs Tariff Act, 1975 as amended in 1995 and thereafter (hereinafter also referred as the Act) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time (hereinafter also referred as the Rules), the Designated Authority (hereinafter also referred to as the Authority) recommended imposition of anti-dumping duty on imports of “Peroxosulphates” (hereinafter also referred to as the subject goods), originating in or exported from China PR, Japan, United States of America and Taiwan.

2. Whereas, the original investigation concerning imports of the subject goods from China and Japan was conducted by the Authority for which anti dumping duties were recommended vide Notification No. 14/1/2006-DGAD dated 20.7.2007. Thereafter, the duties were reviewed in sunset review investigation and recommendations were notified vide Notification No. 15/9/2011-DGAD dated 12.3.2013. Accordingly, Customs Notification No. 11/2013-Customs (ADD) dated 16.5.2013 was issued imposing duties and the same are in force till 15.5.2018.

3. Whereas, another anti dumping investigation was conducted by the Authority against Taiwan, Turkey and USA for which anti dumping duties were recommended vide Notification No. 14/9/2012-DGAD dated 4.3.2014 against Taiwan & USA only. The duties were imposed vide Customs Notification No. 22/2014-Customs (ADD) dated 16.5.2014 and the same are currently in force against USA and Taiwan till 15.5.2019.

4. Whereas, present petition has been filed by M/s Calibre Chemicals Pvt. Limited, M/s VR Persulphates and M/s Yoyo Chemicals for initiation of Sunset Review investigation in terms of Rule 23(1B) for extension of anti-dumping duty on imports of Peroxosulphates from China PR, Japan, USA and Taiwan.

5. Whereas, the Authority has come to a decision, after examination of facts and data as furnished in the petition, that the imports from Japan and Taiwan are not being dumped causing any injury or likely to cause injury to the domestic industry in case of cessation of present anti dumping duties. However, based on the

facts and data the Authority is of the opinion that there is a need to review for continued imposition of the duties in force in respect of the subject goods, originating in or exported from the China PR and USA.

Subject Countries

6. The countries involved in the present investigation are China PR and USA.

Product under Consideration

7. The product under consideration in the present investigation is Peroxosulphates and is commonly known as Persulphates. The product under consideration is the same as considered in the original investigations.

8. Persulphates are a group of closely related compounds. These are produced as Alkali Metal salts. The product under consideration is classified in various grades namely Ammonium Persulphates (APS), Potassium Persulphates (PPS) and Sodium Persulphates (SPS). These grades belong to the same family of chemical called persulphates or peroxosulphates. The Chemical Formula of these Persulphates are, respectively, $(\text{NH}_4)_2\text{S}_2\text{O}_8$, $\text{K}_2\text{S}_2\text{O}_8$, $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_8$. The three types of persulphates have the same end-uses as an initiator and oxidizing agent in the textile, cosmetics, chemical industries and for effluent treatment plants. They can be substituted for one another, however, there is industry specific requirement of various grades.

9. Persulphates are classified in Chapter 28 of the Customs Tariff Act, 1975 under HS code 2833 40 00. The classification is however, indicative only and is in no way binding on the scope of the present investigation.

Like Article

10. Rule 2(d) with regard to like article provides as under: -

"like article" means an article which is identical or alike in all respects to the article under investigation for being dumped in India or in the absence of such article, another article which although not alike in all respects, has characteristics closely resembling those of the articles under investigation;

11. Petitioners have claimed that there is no known difference in subject goods exported from subject countries and that produced by the Indian industry. Both the products have comparable characteristics in terms of parameters such as physical & chemical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification, etc.

Domestic Industry & Standing

12. The petition has been filed by M/s Calibre Chemicals Pvt. Limited, M/s VR Persulphates and M/s Yoyo Chemicals. The petitioner companies namely M/s Calibre Chemicals Pvt. Limited and M/s VR Persulphates have provided complete financial information in the petition which has been considered for analysing prima facie dumping and consequent injury to the domestic industry. The third petitioner M/s Yoyo Chemicals had not submitted complete information, hence they have been considered for DI standing, however, their data was not considered for analysis of dumping and injury. During the course of investigation, they will be given opportunity to submit complete data which can then be considered before finalizing the outcome of investigation.

13. It has been found that the production of petitioner companies is 86% of Indian production of the subject goods in the Country. On the basis of information furnished, the Authority notes that the petitioner companies have not made any imports of the subject goods from the subject countries during the POI. Therefore, the Authority has considered the petitioner companies as Domestic Industry within the meaning of the Rule 2(b) of the Rules and the application satisfies the criteria of standing in terms of Rule 5 of the Rules supra.

Initiation of Sunset Review

14. Whereas, in view of the duly substantiated application filed and in accordance with Section 9 A (5) of the Act, read with Rule 23 of the Anti-dumping Rules, the Authority hereby initiates a Sunset review investigation to review the need for continued imposition of the duties in force in respect of the subject goods, originating in or exported from the subject countries and to examine whether the expiry of existing duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury to the Domestic Industry.

Period of Investigation

15. The period of investigation (POI) proposed by the applicants was from 1st October 2016–30th September 2017 (12 Months) and the injury investigation period was for the periods April 2014 to March 2015, April 2015 to March 2016 and April 2016 to March 2017. The data beyond POI will also be examined to determine the likelihood of dumping and injury.

Procedure

16. The review will cover all aspects as notified under Notification No. 15/9/2011-DGAD dated 12.3.2013 and Notification No. 14/9/2012-DGAD dated 4.3.2014.

17. The provisions of Rules 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19 and 20 of the Rules supra shall be mutatis mutandis applicable in this review.

18. While submitting questionnaire response, producer/ exporter may have to demonstrate prevalence of market condition related to manufacture, production and sale of subject good in the domestic market and in export to India and other countries. For this purpose, the producer/exporter, may clarify and provide sufficient information on the following:

- a) Decision in regard to price, cost, input including raw material, cost of technology and labour, output, sales and investment, are made in response to market signal reflecting supply and demand and without significant state interference and weather cost of major inputs substantially reflect market value.
- b) Production costs and financial situation does not suffer from any distortion.
- c) The producer/exporter are subject to bankruptcy and property law which guarantees legal certainty and stability for the operation of the firms.
- d) Exchange rate conversions are carried out at the market rate.

Submission of Information

19. The known exporters in the subject countries, the Government of the subject countries through its embassy in India, the importers and users in India known to be concerned with the product are being addressed separately to submit relevant information in the form and manner prescribed and to make their views known to the Authority at the following address:

Government of India
Ministry of Commerce and Industry
Department of Commerce
Directorate General of Anti-Dumping and Allied Duties
4th Floor, Jeevan Tara Building
5, Parliament Street, New Delhi – 110001

20. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the prescribed form and manner within the time limit set out below. Any party making any confidential submission before the Authority is required to submit a non-confidential version of the same to be made available to the other parties.

Time Limit

21. Any information relating to the present review and any request for hearing should be sent in writing so as to reach the Authority at the address mentioned above not later than forty days (40 Days) from the date of publication of this Notification. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the Anti-dumping Rules.

22. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses and offer their comments to the Domestic

Industry's application regarding the need to continue or otherwise the Anti-dumping measures within 40 days from the date of initiation of this investigation.

Submission of information on confidential basis

23. In case confidentiality is claimed on any part of the questionnaire response/ submissions, the same must be submitted in two separate sets (a) marked as Confidential (with title, index, number of pages, etc.) and (b) other set marked as Non- Confidential (with title, index, number of pages, etc.). All the information supplied must be clearly marked as either "confidential" or "non-confidential" at the top of each page and accompanied with soft copies.

24. Information supplied without any confidential marking shall be treated as non-confidential and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect any such non-confidential information. Two (2) copies of the confidential version and two (02) copies of the non-confidential version must be submitted by all the interested parties.

25. For information claimed as confidential, the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed and/or why summarization of such information is not possible.

26. The non-confidential version is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out /summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on confidential basis. However, in exceptional circumstances, parties submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summarization; a statement of reasons why summarization is not possible must be provided to the satisfaction of the Authority.

27. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.

28. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without a good cause statement on the confidentiality claim may not be taken on record by the Authority. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided; shall not disclose it to any party without specific authorization of the party providing such information.

Inspection of public file

29. In terms of rule 6(7) of the Rules, any interested party may inspect the public file containing non-confidential version of the evidences submitted by other interested parties.

Non-cooperation

30. In case any interested party refuses access to and otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may declare such interested party as non-cooperative and record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

SUNIL KUMAR, Addl. Secy. and Designated Authority